जून, 2026 , वर्ष : 47 अंक : 6

www.indiatibet.net

# तिब्बत देश

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका

AI generated image (GPT Image 2)

मूल्य :10 रू , वार्षिक : 100 रू

# तिब्बत देश

जून, 2026 , वर्ष : 47 अंक : 6

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित तिब्बत के बारे में सही जानकारी के साथ हर महीने आपके हाथो में

**प्रधान संपादक**
**ताशी देकि**

**सलाहकार संपादक**
प्रो. श्यामनाथ मिश्र , डा. अतुल कुमार

**प्रबंध संपादक**
मिग्मार छमचो

**वितरण प्रबंधक**
**नावांग छोडेंन**

**संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय :**
भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र
एच -१० लाजपत नगर -३
नई दिल्ली -११००२४, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचरों से संपादक, प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख अवश्य करें ।

सिक्योंग ने सभा को संबोधित किया

## समाचार -

०१. सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने कर्नाटक के ३४वें मुख्यमंती श्री डी.के. शिवकुमार को बधाई दी 2

०२. बर्लिन में तीसरे अंतरराष्ट्रीय उग्यूर फोरम में सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने तानाशाही के खिलाफ मिलकर संघर्ष का आह्वान किया 2

०३. इंडिया हैबिटेट सेंटर द्वारा आयोजित व्याख्यान में सिक्योंग ने भारत-तिब्बत संबंधों और परम पावन दलाई लामा की विरासत पर चर्चा की 3

०४. सिक्योंग ने इंडिया हैबिटेट सेंटर प्रदर्शनी में परम पावन की चार प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डाला, दिल्ली में शेरिग पार्खंग ट्रस्ट का उद्घाटन किया 5

०५. निर्वासित तिब्बती संसद के १८वें सत्र की पहली बैठक में १७वें कशाग के लिए छह सदस्य चुने गए 6

०६. सचिव जिग्मे शेरिंग नई दिल्ली स्थित परम पावन दलाई लामा ब्यूरो का नया प्रतिनिधि नियुक्त 6

०७. तिब्बत-जापान कार्यालय ने शिकोकू द्वीप के हाग्युजी मंदिर में परम पावन दलाई लामा के जीवन और मिशन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी और वार्तालाप कार्यक्रमों का आयोजन किया 7

०८. चामराजनगर के अतिरिक्त उपायुक्त का कोल्लेगल धोंडेनलिंग तिब्बती बस्ती का दौरा 8

०९. फ्रांसीसी सीनेटर ने राष्ट्रपति मैक्रों से चीन के 'नस्लीय एकीकरण कानून' पर दखल देने की अपील की 8

१०. विश्व शरणार्थी दिवस पर जापान स्थित तिब्बत हाउस की परम पावन दलाई लामा के जीवन और शिक्षाओं की फोटो प्रदर्शनी 9

११. पेरिस में तिब्बत का २५वां सांस्कृतिक महोत्सव 'करुणा वर्ष' के रूप में मनाया गया 10

१२. तिब्बती स्कूल सुविधा प्रदाताओं के लिए तीन दिवसीय एसईई लर्निंग वर्कशॉप संपन्न 11

१३. तिब्बत लॉबी डे २०२६ ने वेस्टमिंस्टर में तिब्बत की आवाज पहुंचाई, तिब्बतियों और समर्थकों ने नौ सांसदों से बातचीत की 12

१४. मीडिया वक्तव्य 13

१५. ब्रुसेल्स में तिब्बती, चीनी असंतुष्ट और लोकतंत्र कार्यकर्ताओं ने तियानमेन चौक नरसंहार की ३७वीं बरसी मनाई 14

१६. तिब्बत लॉबी डे पर वॉशिंगटन डीसी में जुटे २२५ तिब्बती और समर्थक, तिब्बत बिल पास करने की अपील 14

१७. संरा मानवाधिकार प्रमुख ने मानवाधिकार परिषद के सत्र में चीन के 'नस्लीय एकीकरण कानून' को रद्द करने की मांग की 15

१८. आत्मदाह करने वाले तिब्बतियों का स्मरण 16

समाचार -

मुद्रक एवं प्रकाशक
जमयांग दोरजी द्वारा

नोरबू ग्राफ़िक्स , 1/6, बेसमेंट
विक्रम विहार , लाजपत नगर
नई दिल्ली - 110024

तिब्बत के बारे में नियमित जानकारी के लिए भारत - तिब्बत समन्वय केन्द्र की वेबसाइट

coordinator@indiatibet.net

# अपनी बात | नवगठित तिब्बती संसद द्वारा अनुमोदित नये मंत्रिमंडल का शपथ–ग्रहण

**प्रो0 श्यामनाथ मिश्र**
श्री श्याम मंदिर, खेतड़ी
जिला–झुंझुनूं (राजस्थान)
मो.–9079352370
E-mail:- shyamnathji@gmail.com

तिब्बती धर्मगुरु परमपावन दलाईलामा ने तिब्बती समाज में लोकतंत्र की जो गंगा बहाई है उसी का परिणाम है कि तिब्बती समुदाय वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर निर्वासित तिब्बत सरकार की कार्यपालिका एवं विधानपालिका का निर्वाचन सफलतापूर्वक कर रहा है। नवनिर्वाचित 18वीं तिब्बती संसद का दो दिवसीय सत्र 2 एवं 3 जून, 2026 को सम्पन्न हुआ। तिब्बती निर्वाचन आयोग की चुनावी व्यवस्थानुसार सांसदों ने अपने मताधिकार का उपयोग कर संसद के सभापति पद हेतु श्रीमती डोल्मा त्सेरिंग तथा उपसभापति के लिये श्रद्धेय खेम्पो सोनम टेंफेल का निर्वाचन किया। तिब्बत के 17वें कासाग (मंत्रिमंडल) के लिये छः सदस्यों के नाम 18वीं संसद में प्रस्तुत किये गये जिनका अनुमोदन संसद द्वारा कर दिया गया। निर्वासित तिब्बत सरकार के लगातार दूसरी बार निर्वाचित सिक्योंग (राजप्रमुख एवं शासन प्रमुख) माननीय पेंपा त्सेरिंग के मंत्रिमंडल के सभी छः सदस्यों तथा संसद के नवनिर्वाचित सभापति एवं उपसभ‌ापति का शपथ–ग्रहण सर्वोच्च न्याय आयुक्त द्वारा कराया गया। नई संवैधानिक व्यवस्थानुसार सिक्योंग सहित निर्वासित तिब्बत सरकार के सभी उच्च पदों पर शपथ–ग्रहण सर्वोच्च न्याय आयुक्त द्वारा कराया जाता है। शपथ–ग्रहण का यह महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य पहले दलाईलामा के समक्ष होता था। वर्ष 2011 में दलाईलामा स्वयम् अपने समस्त राजनैतिक अधिकारों का त्याग कर चुके हैं।

गत 3 जून को 18वीं संसद द्वारा अनुमोदित 17वीं कासाग के सद. स्यों के शपथ–ग्रहण के बाद दलाईलामा 5 जून को अपने घुटनों की चिकित्सा के लिये दिल्ली चले गये। उनके निजी चिकित्सक एवं अपोलो अस्पताल के डॉ. राजेष महरोत्रा ने दलाईलामा के घुटनों की सफल चिकित्सा और अच्छे स्वास्थ्य की जानकारी दी तो लोगों में अपार खुषी की लहर दौड़ गई। दिल्ली में भारत सरकार में संसदीय कार्य मंत्री एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री माननीय किरेन रिजिजू ने दलाई लामा से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना तथा उनके दर्षन और आषीर्वाद प्राप्त किये। अनेक सांसदों आदि जनप्रति. निधियों तथा अन्य शुभचिंतकों ने भी उन्हें अपनी मंगलकामनायें दीं।

घुटनों की सफल सर्जरी के बाद दलाईलामा 26 जून को लेह पहुँच गये। वहाँ लगभग दो माह का उनका प्रवास है। लेह के कुषोक बकुला रिंपोछे हवाई अड्डा से दलाई लामा के निवास शेवात्सेल फोडांग के मार्ग में सभी जगह लोगों द्वारा दलाईलामा का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। परंपरागत तिब्बती वेषभूषा में लोग खुषी में नाच–गा रहे थे। इस स्वागत–अभिनंदन में विभिन्न मजहब (पंथ, रिलिजन, मत, संप्रदाय, उपासना पद्धति) के लोग शामिल थे। दला. ईलामा यद्यपि बौद्ध धर्मगुरु हैं लेकिन वे सुझाव देते हैं कि प्रत्येक रिलिजन के अनुयाई अन्य सभी रिलिजन का तथा उनके अनुया. इयों का भी सम्मान करें। उनके अनुसार प्रत्येक रिलिजन सिर्फ पूजा एवं प्रार्थना की पद्धति में अन्य रिलिजन से भिन्न है। उनके मतानुसार सभी रिलिजन अर्थात् पंथों में परस्पर समान आदर का भाव ही वास्तविक सेकुलरिजम है। विष्व में शांति, अहिंसा, करुणा एवं सहयोग के लिये सभी मजहब परस्पर सम्मानपूर्ण व्यवहार रखें।

दलाईलामा बौद्ध धर्मगुरु होते हुए भी अन्य पंथों के कार्यक्रमों में प्रसन्नतापूर्वक शामिल होते हैं तथा भगवान् बुद्ध से जुड़े अपने कार्यक्रमों में उन्हें भी ससम्मान शामिल करते हैं। यही कारण है कि उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन हेतु अपनी–अपनी उपासना पद्धति के अनुरूप विभिन्न संप्रदायों के अनुयाई पूजा–प्रार्थना करते रहते हैं। इसीलिये लेह में भी उनके स्वागत–अभिनंदन में विभिन्न रिलिजन के लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी कोई आष्चर्यजनक घटना नहीं है। यह तो दलाईलामा के विभिन्न मतों के बीच सद्भ‌ाव बढ़ाने हेतु कठिन परिश्रम के लगातार बढ़ते रचनात्मक प्रभाव का ठोस प्रमाण है।

जून माह में तिब्बत में चल रही दमनकारी चीनी नीति पर जोरदार अंतरराष्ट्रीय चर्चा भी महत्वपूर्ण है। निर्वासित तिब्बत सरकार के पुनर्निर्वाचित सिक्योंग पेंपा त्सेरिंग ने दिल्ली की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के बाद यूरोप और अमेरिका की यात्रा की। सभी जगह उन्होंने तिब्बत की दर्दनाक आंतरिक स्थिति तथा चीन सरकार के जातीय एकता एवं विकास कानून, जो कि 1 जुलाई, 2026 से लागू होना है, के खतरनाक प्रावधानों से परिचित कराया। चीन के संविधान के अनुसार चीन सरकार सभी अल्पसंख्यकों के संरक्षण एवं विकास हेतु कदम उठाये। चीन में 56 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। इनमें तिब्बती समुदाय भी शामिल है। चीन सरकार 1959 में स्वतंत्र तिब्बत पर अपने अवैध आधिपत्य के समय से ही तिब्बत का चीनीकरण करने में लगी है। वह तिब्बती नामों की जगह स्थानों, संस्थानों, परंपराओं आदि के नाम चीनी भाषा में रख रही है। तिब्बती बच्चों को षड्यंत्रपूर्वक तिब्बतविरोधी तथा चीन समर्थक बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक विरोधी नये कानून की विभिन्न देषों में घोर निंदा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् के 62वें सत्र में इसके उच्चायुक्त वेल्कर तर्क ने इस नये चीनी कानून की तीखी आलोचना करते हुए इसे समाप्त करने की मांग की है। यूरोपीय संघ भी इसी मत का है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चीन सरकार अपने ही संविधान के प्रावधानों के विपरीत जातीय एकता एवं विकास कानून लागू कर सभी अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान और अंततः उनके अस्तित्व को मिटा देना चाहती है। सिक्योंग पेंपा त्सेरिंग ने इस कानून को तिब्बत एवं तिब्बती समुदाय के लिये विनाषकारी बताते हुए इसकी समाप्ति हेतु चीन सरकार को बाध्य करने की विष्व समुदाय से अपील की है। इस नये चीनी कानून के लागू होते ही सभी अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति, इतिहास, मजहब एवं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के सुनियोजित विनाष की गति अधिक बढ़ जायेगी।

## ◆ ०१. सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने कर्नाटक के ३४वें मुख्यमंत्री श्री डी.के. शिवकुमार को बधाई दी

**०३ जून, २०२६**

**धर्मशाला।** केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने सीटीए और तिब्बती लोगों की ओर से कर्नाटक के आठ बार विधायक रहे श्री डी.के. शिवकुमार को कर्नाटक के ३४वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर हार्दिक बधाई दी।

अपने बधाई संदेश में सिक्योंग ने लिखा, 'मुख्यमंत्री के पद पर आपका आना आपकी बेहतरीन संगठनात्मक नेतृत्व क्षमता और विकास-उन्मुख पहलों के कारण व्यापक रूप से सराहा जा रहा है, जो कर्नाटक के लोगों की आकांक्षाओं का एक सशक्त प्रतीक हैं।'

सिक्योंग ने आगे कहा, 'कर्नाटक और तिब्बती लोगों के बीच गहरे ऐतिहासिक और मानवीय संबंध हैं, जो पीढ़ियों से कायम हैं। १९५९ में परम पावन दलाई लामा के भारत आने के बाद, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एस. निजलिंगप्पा ने १९६० में बायलाकुप्पे में लगभग ३,००० एकड़ जमीन उदारतापूर्वक आवंटित करके एक अहम भूमिका निभाई थी। इस ऐतिहासिक कदम से ही तिब्बतियों ने निर्वासन में पहली बड़ी तिब्बती बस्ती बसाई, जिससे हजारों लोगों को अपना जीवन फिर से शुरू करने और अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का मौका मिला। यह करुणा का एक ऐसा गहरा कार्य था, जिसे परम पावन दलाई लामा ने बहुत सराहा।'

उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देते हुए सिक्योंग ने अंत में लिखा, 'जिस तरह श्री निजलिंगप्पा की विरासत ने करुणा और विकास के एक परिवर्तनकारी युग की नींव रखी, हमें विश्वास है कि आपका कार्यकाल भी कर्नाटक के लोगों और तिब्बती समुदाय दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। आपके कुशल नेतृत्व में हम अपनी अटूट दोस्ती और आपसी सम्मान के और मजबूत होने की उम्मीद करते हैं।'

## ◆ ०२. बर्लिन में तीसरे अंतरराष्ट्रीय उग्यूर फोरम में सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने तानाशाही के खिलाफ मिलकर संघर्ष का आह्वान किया

१४ जून, २०२६

बर्लिन (जर्मनी), १२ जून। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने बर्लिन के ओसीएके होटल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय उग्यूर फोरम (आईयूएफ) के दौरान 'टेस्टिंग ऑफ ग्लोबल रेड लाइन्स : ईस्ट तुर्किस्तान, तिब्बत एंड ताइवान' विषय पर एक उच्च स्तरीय पैनल चर्चा में हिस्सा लिया।

इस खास पैनल चर्चा में यूरोप और एशिया के जाने-माने राजनीतिक नेता और प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें बोरिस मिजातोविच, जिरी ओबेरफाल्जर, ओलिवियर फॉरे, डॉ. क्लेमेंट रुए-शेंग गु और एंटोनेट गुहल शामिल थे।

चर्चा के दौरान, सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने परम पावन १४वें दलाई लामा के उत्तराधिकार और पुनर्जन्म की सदियों पुरानी तिब्बती बौद्ध परंपरा को प्रभावित करने की चीनी सरकार की कोशिशों को लेकर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय चिंताओं पर बात की।

सिक्योंग ने इस बात पर जोर दिया कि अगले महीने अपना ९१वां जन्मदिन मनाने जा रहे परम पावन दलाई लामा हाल के वर्षों में घुटने की सर्जरी के बावजूद मानवता की सेवा में सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि परम पावन रोजाना सैकड़ों लोगों से मिलते हैं। वे करुणा, शांति और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के अपने आजीवन मिशन के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने बताया कि परम पावन ने दलाई लामा नामक संस्था के भविष्य के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है। दुनिया भर के तिब्बतियों और बौद्धों द्वारा इस परंपरा को जारी रखने की मांग का जवाब देते हुए परम पावन ने पुष्टि की कि उनके भविष्य के पुनर्जन्म को उजागर करने की जिम्मेदारी 'गाडेन फोडरंग ट्रस्ट' की होगी, जो दलाई लामा से संबंधित मामलों की देखरेख के लिए स्थापित पारंपरिक संस्था है।

सिक्योंग ने पुनर्जन्म की प्रक्रिया पर कब्जा जमाने की चीनी सरकार की कोशिशों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर नास्तिक देश का किसी धार्मिक नेता के पुनर्जन्म को तय करने की शक्ति का दावा करना विरोधाभासी है। उन्होंने कहा कि इस तरह का दखल तिब्बती बौद्ध धर्म और धार्मिक स्वतंत्रता के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करता है।

बीजिंग के इस रुख पर कि दलाई लामा का अगला पुनर्जन्म तिब्बत या चीन के भीतर ही खोजा जाना चाहिए, सिक्योंग ने परम पावन के उस बयान को दोहराया कि अगर तिब्बत और चीन आजाद नहीं रहते हैं, तो वे किसी आजाद देश में पुनर्जन्म लेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुनर्जन्म की अवधारणा आध्यात्मिक पसंद पर आधारित है

और इसे राजनीतिक अधिकारियों द्वारा तय नहीं किया जा सकता।

सिक्योंग ने ११वें पंचेन लामा के मामले पर भी बात की। ११वें पंचेन लामा को १९९५ में परम पावन दलाई लामा ने मान्यता दी थी, लेकिन मान्यता मिलने के कुछ ही समय बाद वे गायब कर दिए गए और आज भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि चीनी सरकार द्वारा राजनीतिक मकसद से किसी दूसरे पंचेन लामा को नियुक्त किया गया है और तिब्बती लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं।

इसके अलावा, सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने तिब्बत की स्थिति के बारे में चीन के ऐतिहासिक दावों को चुनौती दी। चीनी विद्वान प्रोफेसर लाओ हांग-शांग की विस्तृत रिसर्च का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि युआन, मिंग और किंग राजवंशों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस दावे का समर्थन नहीं करते कि तिब्बत प्राचीन काल से ही चीन का अभिन्न अंग रहा है। उन्होंने तिब्बत की राजनीतिक स्थिति के बारे में लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियों को दूर करने के लिए ऐतिहासिक सबूतों और विद्वानों द्वारा किए गए शोध अध्ययनों के महत्व पर जोर दिया।

सिक्योंग ने तथाकथित 'गोल्डन अर्न' प्रणाली को समर्थन में बीजिंग के भरोसे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हाल के ऐतिहासिक अध्ययनों में ऐसे पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, जो यह साबित कर सकें कि तिब्बती पुनर्जन्म लेने वाले लामाओं की पहचान के लिए पारंपरिक रूप से इस प्रणाली की जरूरत थी।

सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने मजाकिया लहजे में पुनर्जन्म पर चीन के दावों के जवाब में परम पावन दलाई लामा की मजेदार प्रतिक्रिया को याद किया। परम पावन ने कहा है कि अगर चीनी कम्युनिस्ट नेता सचमुच पुनर्जन्म में रुचि रखते हैं, तो उन्हें दलाई लामा के पुनर्जन्म का पता लगाने की कोशिश करने से पहले बौद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहिए और चीन के दिवंगत नेताओं के पुनर्जन्म की खोज करनी चाहिए।

सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने भविष्य में भी तिब्बती बौद्ध परंपरा की रक्षा और दलाई लामा के उत्तराधिकार की प्रक्रिया की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने पहले ही तिब्बत से जुड़े अपने कानूनों में दलाई लामा के पुनर्जन्म की मान्यता से संबंधित प्रावधान शामिल कर लिए हैं और अन्य लोकतांत्रिक देशों को भी ऐसे ही कदम उठाने के लिए आगे आना चाहिए।

सिक्योंग ने अपनी बात खत्म करते हुए तिब्बतियों, उग्यूरों, मंगोलियाई लोगों, हांगकांग के लोगों, ताइवानियों, लोकतंत्र के समर्थकों और चीनी सरकार की कुनीतियों से प्रभावित अन्य समुदायों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने मानवाधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए बेहतर तालमेल, रणनीतिक योजना और सामूहिक कार्रवाई का आग्रह किया।

सिक्योंग ने कहा, 'हमें सबसे पहले बड़े मकसद को समझना होगा। अगर जरूरत पड़ी, तो हमें एक साथ आना होगा और यह दिखाना होगा कि आजादी पसंद करने वाले लोग आम चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट हो सकते हैं।' पैनल ने तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान और चीनी सरकार की नीतियों से प्रभावित अन्य क्षेत्रों में धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक संरक्षण और आत्म-निर्णय के अधिकार को लेकर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय चिंता पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की वकालत करने वाले समुदायों के बीच वैश्विक एकजुटता के महत्व को भी रेखांकित किया।

पैनल चर्चा के बाद सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने बर्लिन में डोरोथियनस्ट्रासे १०० में जर्मन बुंडेस्टाग (राष्ट्रीय संसद) के सदस्य और शिक्षा, परिवार मामले, वरिष्ठ नागरिक, महिला और युवा मामलों के संघीय मंत्री के संसदीय राज्य सचिव माननीय माइकल ब्रांड से मुलाकात की।

बैठक के दौरान, सिक्योंग ने परम पावन दलाई लामा के हालिया ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी और तिब्बत से जुड़े प्रचार और जुड़ाव के लिए भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की। माननीय माइकल ब्रांड ने तिब्बती मुद्दे के प्रति अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया और तिब्बत तथा तिब्बती लोगों के लिए अपना समर्थन जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।

इसके बाद दोपहर में सिक्योंग और उनके प्रतिनिधिमंडल ने जर्मन संघीय विदेश कार्यालय के अधिकारियों से मुलाकात की। चर्चा तिब्बत में मौजूदा स्थिति, मानवाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और तिब्बती मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए चल रहे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से जुड़े कई प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित रही।

## ◆ ०३. इंडिया हैबिटेट सेंटर द्वारा आयोजित व्याख्यान में सिक्योंग ने भारत-तिब्बत संबंधों और परम पावन दलाई लामा की विरासत पर चर्चा की

**१० जून, २०२६**

नई दिल्ली। 'अंतरराष्ट्रीय करुणा वर्ष' के उपलक्ष्य में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने ०९ जून २०२६ को नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में 'परम पावन दलाई लामा की भारत को गुरु दक्षिणा' विषय पर चर्चा में भाग लिया। 'हैबिटेट लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर' द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला के इस सत्र का संचालन जाने-माने तिब्बत विशेषज्ञ और 'सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट (चास)' के चेयरमैन विजय क्रांति ने किया और इसकी अध्यक्षता इंडिया हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर प्रो. डॉ. के.जी. सुरेश ने की।

इस व्याख्यान में भारत और दुनिया के लिए परम पावन दलाई लामा के अहम योगदान के बारे में सिक्योंग को सुनने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों से आए १२० से ज्यादा लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में परम पावन दलाई लामा के कार्यालय के प्रतिनिधि जिग्मे जुग्ने, सचिव ताशी देकि और भारत में चेक गणराज्य की राजदूत डॉ. एलिस्का जिगोवा भी मौजूद थीं। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक तरीके से दीया

जलाकर हुई, जिसके बाद प्रो. डॉ. के.जी. सुरेश ने मुख्य अतिथि सिक्योंग पेन्पा शेरिंग को स्मृति-चिह्न भेंट किया।

व्याख्यान की शुरुआत में इंडिया हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर प्रो. डॉ. के.जी. सुरेश ने सिक्योंग पेन्पा शेरिंग का स्वागत किया और परम पावन दलाई लामा के मार्गदर्शन और विजन के तहत उनके नेतृत्व के दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने भारत में तिब्बती समुदाय को एक शांतिप्रिय समुदाय के रूप में मान्यता दी और अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान को सफलतापूर्वक बनाए रखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान का जिक्र किया। सेंटर द्वारा 'अंतरराष्ट्रीय करुणा वर्ष' को मनाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'हम करुणा को सिर्फ एक आध्यात्मिक मूल्य के तौर पर नहीं, बल्कि एक सामंजस्यपूर्ण समाज को और टिकाऊ बनाने के बुनियादी सिद्धांत के तौर पर देखते हैं।' व्याख्यान के मूल विषय पर लौटते हुए उन्होंने कहा, 'परम पावन (दलाई लामा) ने हमेशा भारत को गुरु के रूप में देखा है। हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और अपने गुरु को गुरु-दक्षिणा (आभार का प्रतीक) देते हैं।' साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि कई भारतीय इस बात से अनजान हैं कि तिब्बतियों ने दशकों से भारत में रहने के बावजूद देश के लिए कितना अहम योगदान दिया है।

व्याख्यान का विषय प्रवेश कराते हुए विजय क्रांति ने तिब्बत के साथ अपने लंबे जुड़ाव और १९७२ में परम पावन दलाई लामा के साथ हुए अपने पहले इंटरव्यू को याद किया। उन्होंने तिब्बती समुदाय को 'दुनिया के सबसे अनुशासित शरणार्थी समुदायों में से एक' बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में फैली कम आबादी के बावजूद इस समुदाय ने अपनी आजादी और मातृभूमि के लिए मजबूती से आवाज उठाते हुए अपने मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उन्होंने इस मजबूती का श्रेय समुदाय की एकता, अनुशासन और परम पावन दलाई लामा के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया। क्रांति ने कहा कि उन्हें इस बात की बहुत तारीफ है कि कैसे तिब्बतियों ने अपनी मातृभूमि खोने और निर्वासन में भारी कठिनाइयां झेलने के बाद अपने समुदाय को फिर से खड़ा किया और अपने धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थानों को नए सिरे से सक्रिय किया।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के बारे में बात करते हुए क्रांति ने कहा कि 'रेल, डाक और जेल को छोड़कर' सीटीए के पास सरकार के बाकी सभी स्तंभ और विभाग हैं, साथ ही एक सफल चुनावी व्यवस्था और अनुशासित संचालन प्रक्रियाएं भी हैं। उन्होंने समुदाय की संस्थागत मजबूती के उदाहरण के तौर पर तिब्बती लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जिक्र किया और बताया कि सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने हाल के चुनावों में गुप्त मतदान प्रणाली के जरिए निर्णायक जीत हासिल की और अपने दूसरे कार्यकाल के लिए मजबूत जनादेश प्राप्त किया।

व्याख्यान के विषय पर बात करते हुए सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने समझाया कि गुरु दक्षिणा का अर्थ है गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान और विवेक के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करना। उन्होंने कहा कि भारत में तिब्बतियों के योगदान पर किसी भी चर्चा को सबसे पहले भारत और तिब्बत के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के नजरिए से समझा जाना चाहिए। भारतीय स्रोतों से बौद्ध धर्म के प्रसार और तिब्बती लिपि के विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे तिब्बती बौद्ध धर्म प्राचीन भारतीय ज्ञान, दर्शन और विद्वता से विकसित हुआ। उन्होंने शांतरक्षित, अतिशा, नागार्जुन और अन्य सत्रह महान श्रद्धेय भारतीय गुरुओं को श्रद्धांजलि दी, जिनकी शिक्षाओं ने तिब्बती बौद्ध परंपराओं को आकार दिया। तिब्बत को भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणालियों का संरक्षक बताते हुए उन्होंने कहा कि तिब्बतियों ने मनोविज्ञान, नैतिकता, करुणा और बौद्ध दर्शन से जुड़ी अमूल्य परंपराओं को संजोकर रखा है। उन्होंने कहा, 'तिब्बतियों के लिए हमने प्राचीन भारतीय ज्ञान का एक हिस्सा संजोकर रखा है। आज अगर कोई बौद्ध धर्म का पूरी तरह से अध्ययन करना चाहता है, तो तिब्बती ही एकमात्र ऐसी भाषा है, जिसमें इसका पूरा अध्ययन किया जा सकता है।' उन्होंने यह भी बताया कि इन प्राचीन ग्रंथों को डिजिटल रूप देने की कोशिशें चल रही हैं। 'यह सब भारत की वजह से ही हो पाया है।'

निर्वासन में तिब्बतियों के अनुभव पर बात करते हुए सिक्योंग ने भारत और उसके नेताओं का बहुत आभार जताया कि उन्होंने अपनी मातृभूमि से विस्थापित होने के बाद तिब्बतियों को शरण दी। उन्होंने कहा, 'भारत सरकार की मदद के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं होता।' उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारत के लोगों को इसका श्रेय दिया कि उन्होंने तिब्बतियों को निर्वासन में भी अपने धर्म, संस्कृति और पहचान को बनाए रखने में मदद की। उन्होंने कहा कि हालांकि कम्युनिस्ट चीन के हाथों तिब्बत की आजादी छिन जाना एक ऐतिहासिक त्रासदी थी, लेकिन निर्वासन ने परम पावन दलाई लामा को अहिंसा, करुणा और दया के मूल्यों को दुनिया भर में फैलाने का मौका भी दिया। उन्होंने कहा, 'आभार के तौर पर हम कह सकते हैं कि निर्वासन में आने के बाद हम बौद्ध धर्म को वापस भारत लाए हैं।'

परम पावन को प्राचीन भारतीय ज्ञान का वैश्विक दूत बताते हुए सिक्योंग ने कहा कि परम पावन दलाई लामा अक्सर खुद को 'भारत का बेटा' कहते हैं और उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन इसी देश में बिताया है। मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के प्रति तिब्बती आंदोलन की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि तिब्बती तब तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक तिब्बत के अंदर रहने वाले तिब्बती आजाद नहीं हो जाते, साथ ही वे बातचीत के जरिए ऐसा समाधान खोजने की कोशिश करेंगे

जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो और तिब्बत विवाद का स्थायी समाधान ला सके।

सिक्योंग ने तिब्बत के रणनीतिक और पर्यावरणीय महत्व पर भी जोर दिया और बताया कि तिब्बती पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां भारत सहित पूरे एशिया में करोड़ों लोगों की जीवन-रेखा हैं। उन्होंने तिब्बत में चीनी सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही निगरानी, प्रतिबंधों और आत्मसात करने की नीतियों पर चिंता जताई और इस बात पर जोर दिया कि तिब्बत का भविष्य भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से गहराई से जुड़ा हुआ है। तिब्बती आंदोलन के संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि तिब्बती भारत के समर्थन और सद्भावना के साथ अपने प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने छह दशकों से ज्यादा समय से निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों को शरण देने और उनकी देखभाल करने में 'माता-पिता जैसी भूमिका' निभाई है।

अपने संबोधन के बाद सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों और कुछ मीडिया प्रतिनिधियों के साथ सवाल-जवाब के सत्र में हिस्सा लिया।

## ◆ ०४. सिक्योंग ने इंडिया हैबिटेट सेंटर प्रदर्शनी में परम पावन की चार प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डाला, दिल्ली में शेरिग पार्खंग ट्रस्ट का उद्घाटन किया

**२६ जून, २०२६**

**दिल्ली।** यूरोप और अमेरिका में अपने कार्यक्रम संपन्न कर लौटे सीटीए के सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने २५ जून को दिल्ली में नए रूप में तैयार शेरिग पार्खंग ट्रस्ट का दौरा किया और इंडिया हैबिटेट सेंटर में परम पावन महान १४वें दलाई लामा के जीवन और विरासत पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

शेरिग पार्खंग ट्रस्ट की यात्रा के दौरान सिक्योंग ने ट्रस्ट के नए कार्यालय का उद्घाटन भी किया और इसके प्रकाशन, प्रशासन और वितरण विभागों का अवलोकन किया। सिक्योंग ने कर्मचारियों को फिर से याद दिलाया कि ट्रस्ट की स्थापना मूल रूप से तिब्बती धर्म और संस्कृति को संरक्षित करने के खास मकसद से की गई थी। उन्होंने ट्रस्ट का प्रबंधन कैसे किया जाए और इसकी लंबे समय तक चलने की क्षमता सुनिश्चित करने के तरीकों को खोजने की जरूरत पर भी मार्गदर्शन दिया।

सिक्योंग के साथ नई दिल्ली में परम पावन दलाई लामा ब्यूरो के प्रतिनिधि जिग्मे जुग्ने, सचिव जिग्मे शेरिंग (जो जल्द ही अगले महीने ब्यूरो के नए प्रतिनिधि का पद संभालेंगे), ब्यूरो की सचिव ताशी देकि और प्रोटोकॉल अधिकारी तेनजिन पासंग भी मौजूद थे।

दोपहर बाद सिक्योंग और उनके सहयोगी परम पावन दलाई लामा के जीवन और विरासत पर आधारित फोटो प्रदर्शनी के उद्घाटन में शामिल होने के लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर पहुंचे। यह कार्यक्रम दिल्ली घोटोन आयोजन समिति द्वारा 'करुणा वर्ष' समारोहों के तहत आयोजित किया गया, जो परम पावन की ९०वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महासचिव शार्त्से खेनसुर रिम्पोछे जांगचुप चोएडेन, वरिष्ठ भारतीय पत्रकार और तिब्बत मामलों के जानकार विजय क्रांति, दिल्ली साम्येलिंग तिब्बती बस्ती अधिकारी दोरजी शेरिंग और स्थानीय घोटोन आयोजन समिति के सदस्य भी शामिल हुए।

ब्यूरो की सचिव ताशी देकि ने इस कार्यक्रम की शुरुआत में प्रदर्शनी के मुख्य विषयों के बारे में संक्षेप में बताया। उन्होंने यह जानकारी दी कि कैसे यह परम पावन के असाधारण जीवन और वैश्विक शांति के साथ-साथ तिब्बती सांस्कृतिक और धार्मिक विरासतों के संरक्षण में उनके समर्पित योगदान को उजागर करती है। इसके बाद प्रतिनिधि जिग्मे जुग्ने ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में 'परम पावन' के बचपन से लेकर उनके निर्वासन तक के सफर की पुरानी तस्वीरें शामिल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 'करुणा का वर्ष' के तहत आयोजित यह प्रदर्शनी तिब्बती आध्यात्मिक धर्मगुरु परम पावन १४वें दलाई लामा के दृष्टिकोण का सम्मान करने की पक्की प्रतिबद्धता को दिखाती है।

अपने मुख्य भाषण में, सिक्योंग ने कहा कि हिंसा और संघर्ष से भरी आज की दुनिया में परम पावन दलाई लामा की अहिंसा, शांति और करुणा की शिक्षाएं पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हैं।

उन्होंने कहा कि परम पावन ने चार मुख्य प्रतिबद्धताओं के जरिए अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया है। एक इंसान के तौर पर उनकी पहली प्रतिबद्धता सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। इसके लिए परम पावन ने कई सालों तक एमोरी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर विज्ञान और मानवीय मूल्यों को जोड़ने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम को विकसित करने का काम किया है।

एक बौद्ध भिक्षु के तौर पर उनकी दूसरी प्रतिबद्धता विभिन्न धर्मों के बीच

सद्भाव को बढ़ावा देना है। पिछले वर्षों में परम पावन ने कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा लिया है, धार्मिक सद्भाव पर शिक्षाएं दी हैं और अलग-अलग धार्मिक परंपराओं में आंतरिक मूल्यों को उजागर करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया है।

एक तिब्बती के तौर पर परम पावन की तीसरी प्रतिबद्धता तिब्बती संस्कृति को बचाना और तिब्बत के पर्यावरण की रक्षा करना है। सिक्योंग ने बताया कि तिब्बती संस्कृति शांति और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित है और परम पावन ने हमेशा दुनिया में सकारात्मक योगदान देने की इसकी क्षमता पर जोर दिया है। सिक्योंग ने तिब्बत के पर्यावरणीय महत्व पर भी प्रकाश डाला और बताया कि अक्सर दुनिया का 'तीसरा ध्रुव' कहा जाने वाला तिब्बती पठार एशिया की कई प्रमुख नदियों का स्रोत है। नतीजतन, पूरे उपमहाद्वीप में लाखों लोगों की पेयजल का आधार तिब्बत के पारिस्थितिक स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है।

परम पावन की चौथी प्रतिबद्धता प्राचीन भारतीय ज्ञान को पुनर्जीवित करना है। सिक्योंग ने कहा कि भारत की दार्शनिक विरासत गहरी और व्यापक है और तिब्बती बौद्ध धर्म ने इस समृद्ध बौद्धिक परंपरा को संजोकर रखा है और इसे आगे भी बढ़ाया है।

तिब्बत-चीन मुद्दे पर बात करते हुए सिक्योंग ने फिर से कहा कि परम पावन दलाई लामा के विजन के अनुसार, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन 'मध्यम मार्ग दृष्टिकोण' को अपनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और साथ ही दुनिया भर के लोगों तक परम पावन का संदेश और उनकी शिक्षाएं पहुंचाना जारी रखेगा। उद्घाटन समारोह का समापन ब्यूरो की सचिव ताशी देकि के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।

यह छह दिवसीय प्रदर्शनी आम जनता के लिए ३० जून तक चलेगी।

## ◆ ०५. निर्वासित तिब्बती संसद के १८वें सत्र की पहली बैठक में १७वें कशाग के लिए छह सदस्य चुने गए

**०२ जून, २०२६**

**धर्मशाला।** निर्वासित तिब्बती संसद के १८वें सत्र के पहले दिन निर्वासित तिब्बतियों के चार्टर के अनुच्छेद- २२ के प्रावधानों के तहत केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के १७वें कशाग के छह सदस्यों का चयन किया गया।

अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि 'विधिवत निर्वाचित सिक्योंग द्वारा पद की शपथ लेने के बाद तिब्बती संसद के सामने अपने कशाग के लिए आवश्यक उम्मीदवारों (जिनकी संख्या सात से अधिक न हो) की एक सूची पेश करेंगे। इस सूची में उनके नाम और व्यक्तिगत विवरण शामिल होंगे और इस चार्टर के अनुच्छेद-२१ के प्रावधानों के अनुसार, उनकी योग्यता की पुष्टि के लिए स्पष्टीकरण दिया जाएगा। यदि उन उम्मीदवारों को कलोन के रूप में संसद की सर्वसम्मत मंजूरी मिल जाती है, तो कोई सवाल नहीं उठता। सर्वसम्मत मंजूरी न मिलने की स्थिति में सदन में मौजूद सदस्यों द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार के लिए गुप्त मतदान कराया जाएगा और जो उम्मीदवार कम से कम ५० प्रतिशत वोट हासिल करेगा, उसे कलोन के रूप में निर्वाचित घोषित किया जाएगा। इसके बाद सिक्योंग उन उम्मीदवारों को कलोन के रूप में नियुक्त करेंगे। यदि सिक्योंग द्वारा प्रस्तावित सभी या कोई भी उम्मीदवार कम से कम ५० प्रतिशत वोट हासिल करने में विफल रहता है, तो सिक्योंग को उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार तिब्बती संसद के सामने उम्मीदवारों की एक नई सूची पेश करनी होगी।'

इस प्रावधान के तहत, निम्नलिखित उम्मीदवारों को १७वें कशाग के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया- शेग्याल चुक्या ड्रानी (कसाग सचिव), पाल्डेन धोंडुप (गृह सचिव), शेरिंग धोंडुप ग्यांगसर (वित्त सचिव), उगेन तेनजिन (पूर्व तिब्बती सांसद और वॉयस ऑफ अमेरिका की तिब्बती सेवा के धर्मशाला ब्यूरो के पूर्व प्रमुख), कुंगा ताशी (वॉशिंगटन, डी.सी. स्थित तिब्बत कार्यालय में तिब्बती संपर्क अधिकारी और सीटीए की पूर्व सचिव) और पेमा सो (तिब्बती सांसद और तिब्बत टाइम्स की प्रधान संपादक)।

## ◆ ०६. सचिव जिग्मे शेरिंग नई दिल्ली स्थित परम पावन दलाई लामा ब्यूरो का नया प्रतिनिधि नियुक्त

**१० जून, २०२६**

**धर्मशाला।** कशाग के १० जून, २०२६ के परिपत्र के अनुसार, ब्राजील स्थित 'तिब्बत कार्यालय (तिब्बत हाउस)' के पूर्व प्रतिनिधि सचिव जिग्मे शेरिंग को नई दिल्ली स्थित परम पावन दलाई लामा ब्यूरो का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वे २८ जुलाई २०२६ को इस पद का कार्यभार संभालेंगे।

लोक सेवा आयोग के नियमों और विनियमों के अनुच्छेद १९ (१) के अनुसार, 'तिब्बत कार्यालय' में परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधि

की नियुक्ति कशाग द्वारा सिक्योंग और कलोनों की उपस्थिति में की जाती है।

**सचिव जिग्मे शेरिंग का संक्षिप्त परिचय :**

सचिव जिग्मे शेरिंग का जन्म १९६७ में भारत के लद्दाख में हुआ था और वे अभी कशाग सचिवालय में इतिहास दस्तावेजीकरण और अंतरिम नियुक्ति अनुभाग के निदेशक के तौर पर कार्यरत हैं।

उन्हें सबसे पहले २००५ में सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग (डीआईआईआर) में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। २०१२ में उन्हें अतिरिक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया और उन्होंने डीआईआईआर में तिब्बत टीवी के निदेशक के रूप में भी काम किया।

बाद में, २०१६ में उन्होंने लोक सेवा और चुनाव आयोग के कार्यवाहक सचिव के रूप में कार्य किया। जिग्मे शेरिंग को २०१७ में औपचारिक रूप से लोक सेवा और चुनाव आयोग का सचिव नियुक्त किया गया।

उन्होंने १५ मई, २०१९ को ब्राजील में तिब्बत कार्यालय (तिब्बत हाउस) के प्रतिनिधि का पद संभाला। लैटिन अमेरिका में परम पावन दलाई लामा और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में लगभग सात वर्षों तक सेवा करने के बाद मई २०२६ में उनका तबादला कशाग के इतिहास दस्तावेजीकरण और अंतरिम नियुक्ति अनुभाग में कर दिया गया।

इसके बाद उन्हें १० जून, २०२६ को नई दिल्ली स्थित परम पावन दलाई लामा ब्यूरो के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया।

## ◆ ०७. तिब्बत-जापान कार्यालय ने शिकोकू द्वीप के हाग्युजी मंदिर में परम पावन दलाई लामा के जीवन और मिशन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी और वार्तालाप कार्यक्रमों का आयोजन किया

**०२ जून, २०२६**

**नीहामा।** तिब्बत हाउस, जापान ने शिकोकू द्वीप के एहिमेकेन में हाग्युजी मंदिर में ३० और ३१ मई को दो दिनों तक फोटो प्रदर्शनी और वार्तालाप कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय 'परम पावन दलाई लामा ९०वां जन्मदिन समारोह समिति' और 'एहिमेकेन बौद्ध संघ' ने सहयोग दिया।

मठ के हॉल में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के तिब्बत संग्रहालय द्वारा तैयार किए गए लगभग ४८ फोटो पैनल प्रदर्शित किए गए, जिनमें परम पावन दलाई लामा के जीवन और संघर्ष को दिखाया गया था। साथ ही कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत के सत्र भी आयोजित किए गए। शहर के सौ से अधिक लोगों ने फोटो प्रदर्शनी देखी। कोच्चि और मात्सुयामा जैसे पड़ोसी शहरों के लोगों ने भी प्रदर्शनी देखी और बातचीत के कार्यक्रमों में भाग लिया।

हाग्युजी मंदिर के सदस्य इशिहारा ने बातचीत और प्रदर्शनी के कार्यक्रमों का संचालन किया। उन्होंने कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताया और परम पावन दलाई लामा तथा विश्व शांति और धार्मिक सद्भाव के प्रति उनके कार्यों और योगदान का संक्षिप्त परिचय दिया।

हाग्युजी मंदिर के मुख्य महंथ भिक्षु सैतो उगेन ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए दर्शकों का स्वागत किया और परम पावन दलाई लामा और उनकी शिक्षाओं के साथ अपने जुड़ाव के बारे में बात की। उन्होंने प्रार्थना की कि परम पावन दलाई लामा के जीवन पर आयोजित प्रदर्शनियां और बातचीत दुनिया भर में प्यार, करुणा, अहिंसा और शांति को बढ़ावा देने में मदद करें। परम पावन दलाई लामा ने नवंबर २००९ में हाग्युजी मंदिर का दौरा किया था और लोगों को उनकी यात्रा और शिक्षाएं अभी भी अच्छी तरह याद हैं। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए एक सुखद याद दिलाने वाला अनुभव था, जो पहले शहर में परम पावन दलाई लामा की शिक्षाओं में शामिल हुए थे।

जापान और पूर्वी एशिया के लिए परम पावन दलाई लामा के संपर्क कार्यालय के डॉ. शेवांग ग्यालपो आर्या ने हाग्युजी मंदिर, जन्मदिन समिति और एहिमे बौद्ध संघ को कार्यक्रमों का समर्थन करने और द्वीप पर अधिक लोगों तक परम पावन दलाई लामा के शांति और करुणा के संदेश को पहुंचाने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने दर्शकों को परम पावन दलाई लामा के चार मिशनों- मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना, धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना, तिब्बती संस्कृति का संरक्षण और बौद्ध दर्शन व विज्ञान की प्राचीन भारतीय नालंदा परंपरा का पुनरुद्धार करने के बारे में बताया। उन्होंने आगे बताया कि कैसे परम पावन ने कई मौकों पर कहा है कि भौतिक और वैज्ञानिक रूप से अत्यधिक विकसित जापान को तिब्बतियों जैसे उत्साह के साथ मन के बौद्ध विज्ञान का भी पता लगाना चाहिए। इससे जापान को भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन हासिल करने और विश्व शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में सकारात्मक योगदान देने में मदद मिलेगी।

प्रतिनिधि आर्या के साथ आए तिब्बत हाउस, जापान के कर्मचारी सेल्हा ने परम पावन दलाई लामा की पुस्तकों का जापानी अनुवाद और

कार्यालय तथा तिब्बत मुद्दे पर जानकारी देने वाले ब्रोशर बांटे। आगंतुकों को कोच्चि में होने वाले तिब्बत महोत्सव के साथ क्योटो, हिरोशिमा और ओकायामा में होने वाली प्रदर्शनियों के बारे में भी जानकारी दी गई।

फोटो प्रदर्शनियों और बातचीत में शामिल आगंतुकों और दर्शकों ने यह सुनकर बहुत खुशी जताई कि जापान में 'करुणा वर्ष' का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सकुरा (चेरी ब्लॉसम) के पेड़ लगाए जा रहे हैं और फोटो प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं। इनमें जापानी मठों, कार्यालयों, शिंतो मंदिरों (जिंजा), संस्थानों और आम लोगों की भारी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। समापन समारोह में प्रतिनिधि डॉ. आर्य ने फोटो प्रदर्शनी और बातचीत के कार्यक्रमों के आयोजन में मदद और सहयोग के लिए भिक्षु साइतो उगेन और श्री इशिहारा का धन्यवाद किया और जोरदार तालियों के बीच उन्हें तिब्बती खटक (स्कार्फ) भेंट किए। इस कार्यक्रम को स्थानीय टीवी स्टेशन ने कवर किया और शाम के प्राइम टाइम में प्रसारित किया।

- ***तिब्बत कार्यालय, जापान की रिपोर्ट***

## ◆ ०८. चामराजनगर के अतिरिक्त उपायुक्त का कोल्लेगल धोंडेनलिंग तिब्बती बस्ती का दौरा

**०२ जून, २०२६**

**कोल्लेगल।** चामराजनगर के अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) श्री जवारेगौड़ा टी. (केएएस) ने २७ मई, २०२६ को कोल्लेगल में धोंडेनलिंग तिब्बती बस्ती का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों से बातचीत की, जिनमें धोंडेनलिंग स्थानीय तिब्बती विधानसभा के स्पीकर, कोल्लेगल धोंडेनलिंग सहकारी समिति कार्यालय के अध्यक्ष, तिब्बत मुक्ति साधना के क्षेत्रीय अध्यक्ष और धोंडेनलिंग शिविर के प्रमुख शामिल थे।

दौरे में उन्होंने वहां मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया और इलाके की जमीनी हकीकत को समझा। बाद में उन्होंने बस्ती में मौजूद मठ का भी दौरा किया।

- ***धोंडेनलिंग तिब्बती बस्ती, कोल्लेगल की रिपोर्ट***

## ◆ ०९. फ्रांसीसी सीनेटर ने राष्ट्रपति मैक्रों से चीन के 'नस्लीय एकीकरण कानून' पर दखल देने की अपील की

**०४ जून, २०२६**

**ब्रसेल्स, ०३ जून।** फ्रांसीसी सीनेट में तिब्बत के लिए अंतर-संसदीय समूह की अध्यक्ष जैकलीन यूस्टाचे-ब्रिनियो ने गहरी चिंता जताते हुए राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से अपील की है कि वे चीनी सरकार के सामने 'नस्लीय एकीकरण और प्रगति को बढ़ावा देने वाले' कानून को लेकर देश की चिंता जताएं। यह कानून १२ मार्च, २०२६ को अपनाया गया था और ०१ जुलाई २०२६ से लागू होने वाला है। उनका तर्क है कि यह कानून तिब्बत और अन्य क्षेत्रों में चीन की 'विलयीकरण नीति (स्थानीय लोगों को अपनी संस्कृति में मिलाने की नीति)' को राष्ट्रीय कानून में शामिल करके औपचारिक और मजबूत बनाता है, जिससे तिब्बती सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक अधिकारों का हनन और तेज होता है।

पत्र में चेतावनी दी गई है कि नस्लीय पहचान को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ने वाले प्रावधान शांतिपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों पर निगरानी और प्रतिबंध बढ़ा सकते हैं। इसमें कानून के 'एक्स्ट्रा-टेरिटोरियल' (देश की सीमाओं से बाहर) दायरे पर भी चिंता जताई गई है। आलोचकों का कहना है कि इससे विदेशों में तिब्बतियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं (जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल हैं) का दमन आसान हो सकता है।

यह अपील इस कानून को लेकर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय चिंता के बीच आई है। खास तौर पर, ३० अप्रैल २०२६ को यूरोपीय संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में चीन की 'एकीकरण नीति' और तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा की गई थी और कानून को रद्द करने की मांग की गई थी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने भी चिंता जताई थी।

कानून के 'एक्स्ट्रा-टेरिटोरियल (क्षेत्राधिकार के बाहर)' लागू होने पर भी खास चिंता जताई गई है। इससे चीनी अधिकारी विदेशों में उन लोगों और संगठनों को निशाना बना सकते हैं, जिनकी गतिविधियों को 'राष्ट्रीय एकता' के लिए हानिकारक माना जाता है या जिन पर 'नस्लीय विभेद' पैदा करने का आरोप है। इससे तिब्बती समुदाय के सदस्यों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और यहां तक कि यूरोपीय नागरिकों के खिलाफ सीमा-पार दमन का डर पैदा होता है, साथ ही राज्य की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून को लेकर भी चिंताएं जगती हैं।

पत्र के अंत में तिब्बती लोगों की अपनी पहचान, संस्कृति, भाषा और धार्मिक परंपराओं को संरक्षित करने की कोशिशों के लिए, खासकर परम पावन दलाई लामा की ९०वीं जयंती वाले वर्ष में फ्रांस से समर्थन की मांग की गई है।

परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधि रिग्जिन गेनखांग ने इस संदेश का

स्वागत करते हुए इस जरूरी मुद्दे को फ्रांसीसी राष्ट्रपति के ध्यान में लाने के लिए सीनेटर की कोशिशों की सराहना की। उन्होंने कहा कि तिब्बती लोगों के अधिकारों, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव जरूरी बना हुआ है।

*-ब्रसेल्स स्थित तिब्बत कार्यालय की रिपोर्ट*

## ◆ १०. विश्व शरणार्थी दिवस पर जापान स्थित तिब्बत हाउस की परम पावन दलाई लामा के जीवन और शिक्षाओं की फोटो प्रदर्शनी

**२२ जून २०२६**

**टोक्यो।** जापान स्थित तिब्बत हाउस ने विश्व शरणार्थी दिवस के अवसर पर टोक्यो के बंक्यो सिविक सेंटर में परम पावन दलाई लामा के जीवन और शिक्षाओं पर दो दिवसीय फोटो प्रदर्शनी और वार्ता का आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में शरणार्थियों की आकांक्षाओं का सम्मान और सहयोग करने के लिए २० जून को 'विश्व शरणार्थी दिवस' के रूप में नामित किया है। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए विस्थापित शरणार्थियों से मुक्त स्वतंत्र और दयालु दुनिया के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध होने का भी दिन है।

चीन ने एशिया के रणनीतिक रूप से उच्चभूमि तिब्बत को हथियाने के उद्देश्य से १९५० में सैन्य आक्रमण और धमकी के माध्यम से तिब्बत पर कब्जा कर लिया। क्रूर कब्जे के परिणामस्वरूप लगभग १२ लाख से अधिक तिब्बती मारे गए। ६००० से अधिक मठ और भिक्षुणी विहार नष्ट कर दिये गये। हजारों धार्मिक ग्रंथ और साहित्य जला दिये गये। उस समय २४ वर्ष के तिब्बत के लौकिक और आध्यात्मिक प्रमुख महामहिम दलाई लामा को तिब्बत से भागने और भारत में राजनीतिक शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। लगभग ८०,००० तिब्बती शरणार्थी उनके पीछे-पीछे भारत, नेपाल और भूटान तक पहुंच गये।

परम पावन दलाई लामा के संपर्क कार्यालय के प्रतिनिधि डॉ. सेवांग ग्यालपो आर्य ने इस कार्यक्रम के हिस्सा लेने वालों को तिब्बत के इतिहास और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी और बताया कि निर्वासित तिब्बती समुदाय तिब्बत में जो कुछ भी नष्ट हो रहा है उसे संरक्षित करने और मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसे न्यायपूर्ण बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उन्होंने परम पावन दलाई लामा की चार प्रतिबद्धताओं के बारे में भी बताया, जिनमें मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना, धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना, तिब्बती संस्कृति का संरक्षण और प्राचीन भारतीय नालंदा दर्शन का पुनरुद्धार शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि कैसे ये चार प्रतिबद्धताएं सार्वभौमिक जिम्मेदारी की भावना के साथ एक शांतिपूर्ण और करुणामय वैश्विक समुदाय बनाने की भावना से प्रेरित हैं।

प्रतिनिधि आर्य ने चीनी औपनिवेशिक आवासीय स्कूलों का मुद्दा उठाया और बताया कि कैसे इन स्कूलों में लगभग दस लाख तिब्बती बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। हाल के नस्लीय एकीकरण और प्रगति कानून के बारे में उन्होंने कहा, 'यह कानून एकता और प्रगति के बारे में नहीं है, यह तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान, दक्षिणी मंगोलिया और अन्य अतिक्रमित क्षेत्रों के अल्पसंख्यक नागरिकों की पहचान, भाषा और संस्कृति के उन्मूलन, विलय और विनाश के बारे में है।' उन्होंने बताया कि ०१ जुलाई को तिब्बती, उग्यूर, दक्षिणी मंगोलियाई और हांगकांग के प्रतिनिधि इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि यह कानून उन पर कैसे दुष्प्रभाव डालेगा। इसके साथ ही उन्होंने दर्शकों को बातचीत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

तिब्बत में परम पावन दलाई लामा के प्रारंभिक जीवन, उनके पट्टाभिषेक, शिक्षा, चीनी नेताओं के साथ विचार-विमर्श, भारत पलायन और तिब्बती लोगों की स्वतंत्रता और न्याय के लिए भारतीय और अंतरराष्ट्रीय नेताओं के साथ उनकी बैठकों को याद दिलाने वाले लगभग ४८ फोटो पैनल प्रदर्शित किए गए थे। इसमें एक विशेष खंड है, जहां परम पावन दलाई लामा के चार मिशन वक्तव्यों या उनके जीवन की प्रतिबद्धताओं को प्रासंगिक तस्वीरों के साथ समझाया गया है। वहां एक मेज भी थी, जहां संदर्भ के लिए परम पावन दलाई लामा की पुस्तकों का जापानी अनुवाद प्रदर्शित किया गया था।

प्रदर्शनी को १५० से अधिक लोगों ने देखा। कुछ लोगों ने तिब्बत और भारत की अपनी यात्राओं और परम पावन दलाई लामा की शिक्षाओं में भाग लेने की घटना को याद किया और उस समय की अपनी जानकारी साझा की। दो दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान तिब्बत हाउस, ताशी यांगजोम, सेल्हा, हसेगावा, इनाडा और कर्मा के कर्मचारियों और स्वयंसेवकों ने आगंतुकों का मार्गदर्शन किया और तिब्बत की स्थिति के बारे में बताया। इस अवसर पर तिब्बत और इस कार्यालय के बारे में जानकारी परक सूचना पुस्तिकाएं वितरित की गयीं।

*- जापान स्थित तिब्बत कार्यालय की रिपोर्ट*

## ◆ ११. पेरिस में तिब्बत का २५वां सांस्कृतिक महोत्सव 'करुणा वर्ष' के रूप में मनाया गया

**१५ जून, २०२६**

**पेरिस, १५ जून।** पेरिस में १२ से १४ जून तक आयोजित तिब्बती और हिमालयी लोगों का २५वां सांस्कृतिक महोत्सव बहुत ही सकारात्मक माहौल में संपन्न हुआ। परम पावन दलाई लामा की ९०वीं जयंती के उपलक्ष्य में दुनिया भर में मनाए जा रहे 'करुणा वर्ष' को समर्पित इस महोत्सव में एक वैश्विक मानवीय मूल्य के रूप में करुणा के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

इस महोत्सव में तिब्बत और हिमालयी क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए विद्वानों, आध्यात्मिक गुरुओं, कलाकारों और आम जनता सहित हजारों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पेरिस के लोगों के लिए यह एक ऐसा कार्यक्रम बन गया, जिसमें शामिल होना जरूरी माना गया। साथ ही इस महोत्सव ने पूरे यूरोप से पर्यटकों को भी आकर्षित किया, जिससे यह पेरिस की गर्मियों के सबसे जीवंत और न चूकने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक बन गया।

महोत्सव की शुरुआत शुक्रवार शाम को एक संगीत कार्यक्रम के साथ हुई, जिसके बाद तिब्बती फैशन शो में पारंपरिक परिधानों और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। इसने दर्शकों का मन मोह लिया और आने वाले दिनों के लिए एक प्रेरणादायक माहौल बनाया। कार्यक्रम की शुरुआत में, तिब्बती बच्चों ने पगोडा क्षेत्र में तिब्बती भाषा में कविताएं पढ़ीं, जिससे शाम के उत्सव की एक विचारशील शुरुआत हुई। मुख्य मंच पर होने वाले कार्यक्रमों के बीच, ग्युमेड मठ के भिक्षुओं ने विशेष रूप से भाग लिया और पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे कार्यक्रम में एक आध्यात्मिक आयाम जुड़ गया।

महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन शनिवार, १३ जून को एक पारंपरिक जुलूस के साथ हुआ। इस जुलूस में संघ के सदस्य परम पावन दलाई लामा का चित्र लेकर चल रहे थे। उनके साथ परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधि रिग्जिन गेनखांग, खान अन्ह पगोडा के आदरणीय वरिष्ठ भिक्षु थिच क्वांग दाओ, निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्य थुप्टेन ग्यात्सो और तेनजिन यांगकर, समन्वयक थुप्टेन शेरिंग और तिब्बती संघों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। परम पावन दलाई लामा के चित्र को सिंहासन पर स्थापित करने के बाद, मेहमानों ने 'खटक'(पारंपरिक स्कार्फ) अर्पित किए, परम पावन की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की और स्थल को शुद्ध करने के लिए 'सांग-सोल'(धूप अर्पण अनुष्ठान) किया। शनिवार की शाम, लोबसांग डेलेक की अगुवाई में स्थानीय तिब्बती कलाकारों ने एक शानदार कॉन्सर्ट पेश किया। इस कार्यक्रम ने दर्शकों का मन मोह लिया और लोग देर रात तक नाचते रहे, कॉन्सर्ट में मुख्य रूप से तिब्बती गानों के साथ-साथ लोकप्रिय हिंदी, नेपाली और अंग्रेजी गाने भी शामिल थे।

इस साल के फेस्टिवल की खास बात परम पावन १४वें दलाई लामा के जीवन और विरासत को समर्पित एक विशेष चित्र प्रदर्शनी थी। इन चित्रों के माध्यम से लोगों को एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु के अद्भुत सफर को जानने का मौका मिला, जिनके शांति, अहिंसा और करुणा के संदेश ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है। प्रदर्शनी में तिब्बत में बिताए उनके शुरुआती सालों से लेकर निर्वासन तक उनके जीवन के अहम पलों को दिखाया गया। निर्वासन में वे लगातार शांति, बातचीत, मानवीय मूल्यों और लोगों व देशों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा दे रहे हैं।

'करुणा' पर केंद्रित अंतर-धार्मिक सम्मेलन दूसरा मुख्य आकर्षण था, जिसमें अलग-अलग धर्मों और परंपराओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, हिंदू, सिख, यहूदी, बहाई और अन्य धार्मिक समुदायों के वक्ताओं ने अपनी-अपनी परंपराओं में करुणा की भूमिका पर अपने विचार साझा किए।

हर वक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि करुणा एक बुनियादी सिद्धांत है, जो नैतिक आचरण, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा के प्रति सम्मान का मार्गदर्शन करता है। प्रतिनिधियों ने परम पावन दलाई लामा को श्रद्धांजलि भी दी और करुणा, अंतर-धार्मिक बातचीत और अहिंसा के प्रति उनके जीवन भर के समर्पण को याद किया, साथ ही दुनिया में शांति, समझ और सद्भाव में उनके अहम योगदान को भी रेखांकित किया।

सम्मेलन में हर बातचीत के साथ-साथ करुणा की भावना को दर्शाने वाली कलात्मक प्रस्तुतियां भी हुईं, जिससे चिंतन और कलात्मक अभिव्यक्ति के बीच एक अनोखा संवाद बना। ये प्रस्तुतियां परम पावन दलाई लामा की ९०वीं जयंती के लिए एक दिल को छू लेने वाली श्रद्धांजलि भी थीं, उनके सार्वभौमिक जिम्मेदारी और करुणा के संदेश ने ही पूरे कार्यक्रम को प्रेरित किया।

सम्मेलन ने बातचीत और आपसी समझ की भावना को बढ़ावा दिया और करुणा को एक ऐसे साझा मानवीय मूल्य के रूप में उजागर किया जो सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक मतभेदों से ऊपर है। सोच-समझकर की गई चर्चाओं और विचारों के आदान-प्रदान के जरिए, प्रतिभागियों ने जाना कि कैसे करुणा शांति-निर्माण, सामाजिक एकजुटता और हमारे समय की गंभीर चुनौतियों का सार्थक समाधान खोजने में एक शक्तिशाली ताकत बन सकती है।

झील के किनारे बने मंच पर लोगों ने पारंपरिक तिब्बती सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया, जिनमें तिब्बती ओपेरा, नृत्य और तिब्बत के तीन पारंपरिक प्रांतों- यू सांग, खाम और अमदो के गीत शामिल थे। दिल को छू लेने वाला सबसे भावुक पल तब आया, जब छोटे बच्चों का एक समूह मंच पर आया। रंग-बिरंगे पारंपरिक कपड़ों में सजे-धजे वे साफ-सुथरी कतारों में खड़े थे, उनमें से कुछ तो इतने छोटे थे कि मुश्किल से ही माइक्रोफोन के ऊपर से दिख पा रहे थे। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, उनके प्यारे नृत्य कौशल ने दर्शकों का दिल जीत लिया।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ग्युमेड भिक्षुओं द्वारा रेत का मंडल बनाना भी शामिल था, यह एक हजार साल पुरानी परंपरा है, जो जीवन की

नश्वरता का प्रतीक है।

तिब्बती सांस्कृतिक महोत्सव की २५वीं सालगिरह पर आयोजित इस कार्यक्रम ने तिब्बती संस्कृति को बचाने और समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान, आपसी बातचीत और समझ को बढ़ावा देने के अपने मिशन को फिर से दोहराया। पूरे कार्यक्रम में करुणा का भाव छाया रहा, जिसने लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में इसकी अहमियत और अधिक शांतिपूर्ण और देखभाल करने वाली दुनिया बनाने की इसकी क्षमता के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया।

अलग-अलग व्यवसायों, संगठनों, बौद्ध केंद्रों और कलाकारों द्वारा लगाए गए स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। रंग-बिरंगे स्टॉलों के बीच, ताजे बने तिब्बती व्यंजनों की खुशबू हवा में घुली हुई थी, जो उत्सुक लोगों और खाने के शौकीनों को अपनी ओर खींच रही थी। वहीं, दूसरे स्टॉलों पर तिब्बती और हिमालयी कलाकृतियां और मसाले बेचे जा रहे थे। योग वर्कशॉप के सत्रों ने माहौल में जान डाल दी।

आखिरी दिन सूरज ढलने के साथ महोत्सव में इसके मिशन को फिर से दोहराया गया। इनमें कला, भाषा और वैश्विक एकजुटता के जरिए तिब्बती और हिमालयी संस्कृतियों को न सिर्फ जिंदा रखना, बल्कि उन्हें फलने-फूलने में मदद करना शामिल था।

पूरे फ्रांस, पूरे यूरोप और यहां तक कि अमेरिका जैसे दूर-दराज के इलाकों से भी लगभग ६,००० लोग पेरिस में आयोजित इस महोत्सव में शामिल हुए। कुल मिलाकर, तिब्बती और हिमालयी लोगों का यह सांस्कृतिक उत्सव सफल रहा और इसने लोगों को तिब्बती संस्कृति को गहराई से जानने का मौका दिया।

प्रतिनिधि गेनखांग की देखरेख में पेरिस स्थित 'ब्यूरो डू तिब्बत' के समन्वयक थुप्टेन शेरिंग और 'मेसन डू तिब्बत' के सचिव जिग्मे दोरजी ने महोत्सव का संचालन किया। इसमें अकाउंटेंट तेनजिन नोरधेन और ब्रुसेल्स स्थित 'ब्यूरो डू तिब्बत' से आए यूरोपीय संघ के 'एडवोकेसी ऑफिसर' तेनजिन फुंट्सोक ने भी मदद की।

यह महोत्सव मुख्य रूप से तिब्बती समुदाय, तिब्बत के तीन पारंपरिक प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थानीय तिब्बती संगठनों, एसएफटी, वी-टैग और उन सैकड़ों समर्पित स्वयंसेवकों की मेहनत और सहयोग से संभव हो पाया, जो हर साल अपना समय और ऊर्जा समर्पित करते हैं। समापन समारोह के दौरान प्रतिनिधि रिग्जिन गेनखांग और समन्वयक थुप्टेन शेरिंग ने आयोजकों की कड़ी मेहनत की सराहना की और उनके बहुमूल्य योगदान के लिए दिल से आभार व्यक्त किया।

आभार और घोषणाओं के बाद पारंपरिक 'सर्कल डांस' हुआ, जिसमें दर्शकों ने भी हिस्सा लिया और तिब्बती संस्कृति की समृद्धि का जश्न मनाया।

*- ब्रुसेल्स स्थित तिब्बत कार्यालय की रिपोर्ट*

## ◆ १२. तिब्बती स्कूल सुविधा प्रदाताओं के लिए तीन दिवसीय एसईई लर्निंग वर्कशॉप संपन्न

**०४ जून, २०२६**

**धर्मशाला।** तिब्बती स्कूल फैसिलिटेटर्स (सुविधा प्रदाताओं) के लिए एसईई लर्निंग (सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षण) पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दलाई लामा की लाइब्रेरी और संग्रहालय में २७ से २९ मई तक आयोजित की गई। यह कार्यशाला करुणा पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के साथ चली, जिसे एमोरी यूनिवर्सिटी के 'सेंटर फॉर कॉन्टेंपलेटिव साइंस एंड कंफेशन-बेस्ड एथिक्स' और 'दलाई लामा ट्रस्ट' ने मिलकर आयोजित किया था। इस कॉंफ्रेंस में १७ देशों से २८० प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें ११ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, विभिन्न मठों के शिक्षक और दुनिया भर के वैज्ञानिक शामिल थे।

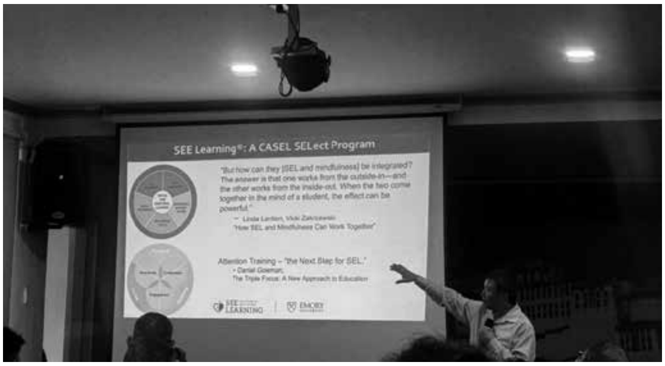


इस कार्यशाला में भारत और नेपाल के शिक्षा विभाग के तहत आने वाले कुल १९ तिब्बती स्कूलों से ३९ प्रतिभागी शामिल हुए। इनमें स्कूल के प्रधानाध्यापक, रेक्टर, प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक, स्नो लायन फाउंडेशन स्कूल के निदेशक, धर्मशाला स्थित एसईई लर्निंग फैसिलिटेटर्स, दर्शन विषय के शिक्षक और पर्यवेक्षक शामिल थे।

शिक्षा विभाग की अतिरिक्त सचिव तेनजिन पेमा ने २९ मई को तिब्बती स्कूलों में एसईई लर्निंग को लागू करने पर भाषण दिया। ३० मई से ०१ जून तक शिक्षा विभाग के एजुकेशनल काउंसिल सेक्शन ने सीटीए ट्रेनिंग सेंटर में एक एसईई लर्निंग कार्यशाला आयोजित की।

एमोरी यूनिवर्सिटी के सह-निदेशक और एसईई लर्निंग प्रोग्राम फैसिलिटेटर सोंडुए सम्फेल ने एसईई लर्निंग के महत्व, इसके फ्रेमवर्क, लचीलापन विकसित करने के तरीकों, भावना नियंत्रण और मानसिक प्रशिक्षण, तंत्रिकाओं के आपस में जुड़े होने, करुणा और सहनशीलता और मानवीय एकता की भावना को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर प्रशिक्षण दिया।

समापन के समय सोंडुए सम्फेल ने कहा कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा विभाग की देखरेख में तिब्बती स्कूलों में पंथनिरपेक्ष नैतिकता और एसईई लर्निंग कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है और लागू

किया जा रहा है। उन्होंने तिब्बती स्कूलों में एसईई लर्निंग परियोजनाओं को और मजबूत करने और एक अच्छा उदाहरण पेश करने के महत्व पर जोर दिया। शिक्षा परिषद के सचिव ने तिब्बती स्कूलों में इन व्यावहारिक परियोजनाओं को लागू करने पर जोर दिया, ताकि शिक्षकों और स्टाफ की मानसिक सेहत और भलाई में सुधार हो सके, साथ ही छात्रों को शिक्षा देने के साथ-साथ उनमें करुणा और सहानुभूति की भावना भी विकसित की जा सके। इसके अलावा, स्कूल में चलाए जा रहे 'टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम' के तहत 'एसईई लर्निंग' को भी शामिल किया गया। शिक्षकों से कहा गया कि वे इस किताब को पढ़ें और उस पर चर्चा करें, धीरे-धीरे इसे समझकर अपनाएं और अपने अच्छे व्यवहार से छात्रों में अच्छे संस्कार डालें।

इसके बाद, शिक्षा विभाग की 'एसईई एजुकेशन फैसिलिटेटर' शेरिंग पाल्जोम ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया और इसके साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। इस ट्रेनिंग को डीएएनआईडीए का सहयोग मिला और इसमें शामिल होने वालों के यात्रा का खर्च दलाई लामा ट्रस्ट ने उठाया।

*- सीटीए के शिक्षा विभाग की रिपोर्ट*

## ◆ १३. तिब्बत लॉबी डे २०२६ ने वेस्टमिंस्टर में तिब्बत की आवाज पहुंचाई, तिब्बतियों और समर्थकों ने नौ सांसदों से बातचीत की

**१८ जून, २०२६**

**लंदन।** तिब्बतियों और तिब्बत समर्थक २६ सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने १७ जून को ब्रिटेन की संसद (हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट) में 'तिब्बत लॉबी डे २०२६' में हिस्सा लिया। उन्होंने नौ सांसदों से बातचीत की और उनसे तिब्बत और तिब्बती लोगों के समर्थन में ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।

'वॉलंटरी तिब्बत एडवोकेसी ग्रुप यूके' (वी-टैग यूके) द्वारा आयोजित और इसके ब्रिटिश नेशनल कोऑर्डिनेटर ताशी सैमुअल्स के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम को 'ऑफिस ऑफ तिब्बत, लंदन' समेत कई सहयोगी संगठनों की ओर से समर्थन दिया गया। इनमें 'इंटरनेशनल तिब्बत नेटवर्क', 'फ्री तिब्बत', 'स्टूडेंट्स फॉर ए फ्री तिब्बत' (इंटरनेशनल और लंदन चैप्टर), 'तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूट' और 'ब्रिटेन में तिब्बती समुदाय' के सदस्य शामिल थे।

इस वार्षिक पक्षधरता कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने 'प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चंस' से पहले सेंट्रल लॉबी में जाकर सांसदों से संपर्क किया। 'प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चंस' सप्ताह के सबसे व्यस्त और चर्चित संसदीय सत्रों में से एक है।

संसद के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद प्रतिभागियों ने कई सांसदों से सफलतापूर्वक बातचीत की। इनमें लेबर पार्टी के लेविशम नॉर्थ के सांसद विकी फॉक्सक्रॉफ्ट सांसद, लेबर पार्टी के आयल्सबरी से सांसद लॉरा किर्क-स्मिथ, कंजर्वेटिव पार्टी, ब्रेनट्री से सांसद और पूर्व विदेश मंत्री सर जेम्स क्लेवरली, लेबर पार्टी के ब्रिस्टल नॉर्थ वेस्ट से सांसद और वित्त विभाग के मुख्य सचिव द राइट ऑनरेबल डैरेन जोन्स, लेबर पार्टी की कोऑपरेटिव, वाल्थमस्टो से सांसद स्टेला क्रीसी, कंजर्वेटिव पार्टी के चिंगफोर्ड और वुडफोर्ड ग्रीन से सांसद सर इयान डंकन स्मिथ और लेबर पार्टी के न्यूपोर्ट ईस्ट से सांसद डेम जेसिका मॉर्डन शामिल थे।

**प्रतिभागियों ने नीति से जुड़ी तीन मुख्य मांगें रखीं:**

०१. चीन के 'नस्लीय एकीकरण और प्रगति को बढ़ावा देने वाले कानून' की निंदा करना और इसके नुकसानदेह प्रावधानों पर जोर देना। ये प्रावधान तिब्बती पहचान को मिटाने में मदद करते हैं और तिब्बती संस्कृति, भाषा और धर्म को व्यक्त करने को अपराध की श्रेणी में डालते हैं। सांसदों से आग्रह किया गया कि वे चीनी सरकार से इस कानून को रद्द करने की मांग करें।

०२. 'प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चंस' बैलेट के लिए आवेदन करके या 'प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चंस' के दौरान पूरक प्रश्न पूछकर तिब्बत में औपनिवेशिक शैली के आवासीय स्कूलों का मुद्दा उठाना। भाग लेने वालों ने इस बात पर चिंता जताई कि ये स्कूल 'बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' के अनुच्छेद- २९ और ३० का उल्लंघन करते हैं और तिब्बती बच्चों को उनकी भाषा, संस्कृति और विरासत से सुनियोजित तरीके से अलग करने की साजिश का हिस्सा हैं।

०३. परम पावन १४वें दलाई लामा के उत्तराधिकार पर उनके अधिकार का सार्वजनिक रूप से समर्थन करें, जिसमें पुनर्जन्म पर ०२ जुलाई

२०२५ के उनके बयान का समर्थन करना भी शामिल है। सांसदों से कहा गया कि वे तिब्बती बौद्ध धर्म की इस पवित्र परंपरा में दखल देने या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए तिब्बती धार्मिक नेताओं को नियुक्त करने की चीनी सरकार की किसी भी कोशिश का विरोध करें।

तिब्बत लॉबी की कार्रवाई का तुरंत नतीजा यह हुआ कि सांसद सर इयान डंकन स्मिथ ने चीन के 'नस्लीय एकीकरण और प्रगति को बढ़ावा देने वाले कानून' की निंदा करते हुए एक कड़ा बयान दिया और तिब्बत तथा तिब्बती लोगों के लिए अपना लगातार समर्थन जारी रखने का भरोसा दिलाया।

संसदीय बैठकों के बाद प्रतिभागी पोर्टकुलिस हाउस के रूम क्यू में इकट्ठा हुए, जिसे ब्रिटिश संसद में तिब्बत के लिए सर्वदलीय संसदीय समूह के अध्यक्ष सांसद क्रिस लॉ (एसएनपी, डंडी सेंट्रल) ने बुक किया था। वहां उनके साथ लेबर पार्टी की ब्रिस्टल ईस्ट से सांसद केरी मैकार्थी और लिबरल डेमोक्रेट की बाथ से सांसद वेरा हॉबहाउस भी शामिल हुईं। दोनों सांसदों ने अभियान की मुख्य मांगों पर चर्चा की, तिब्बत के लिए अपना समर्थन दोहराया और संसद में तिब्बत से जुड़े मुद्दों को उठाना जारी रखने का वादा किया।

मैकार्थी और हॉबहाउस उस चार-सदस्यीय यूके संसदीय प्रतिनिधिमंडल (जिसमें क्रिस लॉ और एलिसिया किर्न्स भी शामिल थे) का हिस्सा थीं, जिसने पिछले महीने लंदन स्थित तिब्बत कार्यालय के कार्यक्रम के तहत धर्मशाला का दौरा किया था। यात्रा के दौरान वे परम पावन १४वें दलाई लामा से मिलीं और सिक्योंग पेन्पा शेरिंग के दूसरे पांच साल के कार्यकाल की शुरुआत के मौके पर आयोजित आधिकारिक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुईं।

प्रतिनिधि शेरिंग यांगकी ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़ने में उनकी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने चीनी शासन के तहत रह रहे तिब्बतियों की ओर से बात करने और यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि उनकी आवाज और संघर्षों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुना जाए।

कार्यक्रम का समापन करते हुए ताशी सैमुअल्स ने प्रतिभागियों को उनके समर्पण के लिए धन्यवाद दिया और लॉबी डे के बाद भी सांसदों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

तिब्बत लॉबी डे- २०२६ का समापन संसद के बाहर एक समूह फोटो सत्र के साथ हुआ। यह पूरे यूनाइटेड किंगडम में तिब्बतियों और समर्थकों द्वारा तिब्बत के मुद्दों को सीधे ब्रिटिश लोकतंत्र के केंद्र तक पहुंचाने की एक और महत्वपूर्ण कोशिश थी।

*- तिब्बत कार्यालय, लंदन की रिपोर्ट*

## ◆ १४. मीडिया वक्तव्य

**२६ जून २०२६**

चीन के पास दलाई लामा के पुनर्जन्म के मामले में दखल देने का कोई ऐतिहासिक, धार्मिक या राजनीतिक अधिकार नहीं है।

कैनबरा स्थित तिब्बत सूचना कार्यालय इस हफ्ते की शुरुआत में क्षेत्रीय अखबारों में छपे चीनी दूतावास द्वारा प्रायोजित विज्ञापन की कड़ी निंदा करता है। इस विज्ञापन का शीर्षक था 'दलाई लामा कैसे दलाई लामा बने: तिब्बती बौद्ध धर्म का एक दिलचस्प इतिहास'। यह खरीदा हुआ दुष्प्रचार अभियान जनमत को गुमराह करने की कोशिश है। इस विज्ञापन में झूठा दावा किया गया है कि दलाई लामा की पहचान और पुनर्जन्म चीन के भीतर ही होना चाहिए और इसके लिए चीनी सरकार की मंजूरी जरूरी है। ये दावे पूरी तरह से बेबुनियाद और बेहद गुमराह करने वाले हैं। ये दुनिया भर के बौद्ध समुदाय और मौलिक मानवाधिकारों के प्रति गहरी अवहेलना दिखाते हैं।

हम ऑस्ट्रेलियाई जनता, मीडिया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों को दोहराना चाहते हैं:

**पुनर्जन्म तय करने का अधिकार पूरी तरह से दलाई लामा के पास है**

जैसा कि परम पावन (दलाई लामा) ने ०२ जुलाई २०२५ को फिर से स्पष्ट किया था, दलाई लामा की संस्था बनी रहेगी और उनके भविष्य के पुनर्जन्म को मान्यता देने का अधिकार केवल गादेन फोडरंग ट्रस्ट (परम पावन दलाई लामा का कार्यालय) के पास है।

**पुनर्जन्म एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, राजनीतिक नहीं।**

पुनर्जन्म या 'तुलकु' (पुनर्जन्म लेने वाले लामा) की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए पहले पिछले और अगले जन्मों के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। इसलिए, पुनर्जन्म लेने वाले लामाओं की पहचान उन आध्यात्मिक और धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिनमें पूर्व जन्मों में चेतना की निरंतरता को स्वीकार किया जाता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नास्तिक शासन है और तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता का सक्रिय रूप से दमन करती है। इसलिए उसके पास इस पवित्र परंपरा में दखल देने का कोई कानूनी, ऐतिहासिक या आध्यात्मिक अधिकार नहीं है।

**नियंत्रण और मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक पैटर्न**

बीजिंग की सरकार द्वारा दलाई लामा को थोपे जाने की महत्वाकांक्षा १९९५ में ११वें पंचेन लामा के अपहरण जैसी ही है, जिनके बारे में जानकारी जबरदस्ती छिपाई गई है। यह तिब्बती सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को मिटाने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है।

हम व्यापक ऑस्ट्रेलियाई समुदाय से आग्रह करते हैं कि वे उन राजनीतिक विचारों के प्रति सतर्क रहें, जिनका मकसद तिब्बती बौद्ध धर्म की पवित्र परंपराओं को कमजोर करना है। तिब्बती आध्यात्मिक नेतृत्व की निरंतरता तिब्बती आध्यात्मिक परंपराओं के आधार पर तय

होगी और तिब्बती लोग बीजिंग द्वारा नियुक्त किसी कठपुतली 'दलाई लामा के पुनर्जन्म' को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

**कर्मा सिंगे**

**प्रतिनिधि**

**तिब्बत सूचना कार्यालय**

**Email: rep.au@tibet.net**

## ◆ १५. ब्रुसेल्स में तिब्बती, चीनी असंतुष्ट और लोकतंत्र कार्यकर्ताओं ने तियानमेन चौक नरसंहार की ३७वीं बरसी मनाई

**०४ जून, २०२६**

**ब्रुसेल्स।** बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में तियानमेन चौक नरसंहार (जिसे ०४ जून की घटना भी कहा जाता है) की ३७वीं बरसी मनाने के लिए ०४ जून को एक सभा आयोजित की गई। लोकतांत्रिक सुधारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे चीनी छात्रों का चीनी सरकार ने १९८९ में इसी तारीख को बेरहमी से दमन किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन 'साइनो यूरो वॉयस' और चीनी संपर्क अधिकारी सांगेय क्याब ने मिलकर किया था।

'१९८९ की भावना को आगे बढ़ाना, लोकतंत्र को बढ़ावा देना और ०४ जून की घटना की ३७वीं बरसी को वैश्विक स्तर पर याद करना' शीर्षक वाली इस बैठक में दुनिया भर से ३० से अधिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और लोकतंत्र समर्थक शामिल हुए। इनमें यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिभागी शामिल थे।

इस बैठक में उपस्थित प्रमुख लोगों में बेल्जियम और यूरोपीय संघ में ताइवान के राजदूत शिएह झी-वेई, यूरोपीय देशों के लिए चीनी संपर्क अधिकारी सांगेय क्याब, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के चीनी डेस्क के प्रधान संपादक जामयांग शेरिंग और तिब्बती मुद्दे के लिए सोशल मीडिया कार्यकर्ता साकार ताशी शामिल थे। इसमें चीनी, उग्यूर और ताइवानी समुदायों के कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी भी मौजूद रहे। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के निर्वाचित नेता सिक्योंग पेन्पा शेरिंग का ऑनलाइन शामिल होना था, लेकिन पहले से तय अन्य व्यस्तताओं के कारण वे शामिल नहीं हो सके।

बैठक की अध्यक्षता सांगेय क्याब ने की। उन्होंने अपने संबोधन में ०४ जून की घटना और ल्हासा में तिब्बती प्रदर्शनकारियों के खिलाफ चीनी सरकार द्वारा पहले किए गए नरसंहार के बीच सीधा ऐतिहासिक संबंध बताया। उन्होंने कहा कि तिब्बती छात्रों ने खुद पूरे चीन में १९८९ के लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने याद दिलाया कि परम पावन दलाई लामा ने तुरंत और सार्वजनिक रूप से इस दमन की निंदा की थी और छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त की थी। तब से केंद्रीय तिब्बती प्रशासन चीन के लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन के समर्थन में खड़ा रहा है। उन्होंने १९८९ के बाद निर्वासन में तिब्बती और चीनी समुदायों के बीच बने मजबूत रिश्ते की भी चर्चा की। उन्होंने कहा, 'उस घटना के बाद कई चीनी लोग निर्वासन में आए और तब से तिब्बती और चीनी लोगों के बीच विचारों के आदान-प्रदान का दौर शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। अब हम न केवल विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, बल्कि एक-दूसरे का सक्रिय रूप से समर्थन भी करते हैं।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आपसी एकजुटता के और मजबूत होने से ३७वीं बरसी का आयोजन और भी खास हो गया।

उसी शाम, ताइवानी दूतावास ने एक डिनर का आयोजन किया, जिसमें ब्रुसेल्स स्थित तिब्बत कार्यालय में प्रतिनिधि रिग्जिन चोडोन गेनखांग, सचिव ताशी वांगडुए, तिब्बती संपर्क अधिकारी धोंडुप ग्यालपो, सांगेय क्याब, साकार ताशी और लोकतंत्र समर्थक कई चीनी कार्यकर्ता शामिल हुए।

यादगार कार्यक्रमों के तहत ०४ जून को बेसल में चीनी दूतावास के सामने एक विरोध प्रदर्शन भी किया गया।

*- ब्रुसेल्स स्थित तिब्बत कार्यालय की रिपोर्ट*

## ◆ १६. तिब्बत लॉबी डे पर वॉशिंगटन डीसी में जुटे २२५ तिब्बती और समर्थक, तिब्बत बिल पास करने की अपील

**११ जून, २०२६**

**वॉशिंगटन डीसी।** अमेरिका में वार्षिक 'तिब्बत लॉबी डे' ०८ और ०९ जून को आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 'नॉर्थ अमेरिकन तिब्बती एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस' में लिए गए फैसलों के आधार पर 'इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत' के नेतृत्व और तिब्बती संघों की भागीदारी से संपन्न हुआ।

'तिब्बत लॉबी डे' में शामिल होने के लिए अमेरिका के २७ राज्यों से २२५ से ज्यादा तिब्बती और तिब्बत समर्थक वॉशिंगटन डीसी में जुटे। उन्होंने अमेरिकी सीनेटरों और कांग्रेस के सदस्यों से 'अश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत ऐक्ट (एएफटीए)' को पास करने और तिब्बत के मुद्दे का समर्थन करने की अपील की। इस साल के अभियान में बड़ी संख्या में युवा तिब्बती छात्रों ने हिस्सा लिया।

०८ जून की शाम को एक स्वागत भोज आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम अमेरिका की स्थापना की २५०वीं वर्षगांठ मनाने, निर्वासित तिब्बती समुदाय और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के राजनीतिक नेता के तौर पर सिक्योंग पेन्पा शेरिंग के दोबारा चुने जाने और १८वीं निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों के चुने जाने का जश्न मनाने के लिए था।

कैपिटल हिल में हुए इस स्वागत भोज में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी शामिल हुईं और लोगों को संबोधित किया। प्रतिनिधि नामग्याल छोडुप और आईसीटी की प्रेसिडेंट तेनचो ग्यात्सो ने भी अपनी बात रखी।

*-वॉशिंगटन डीसी स्थित तिब्बत कार्यालय की रिपोर्ट*

## ◆ १७. संरा मानवाधिकार प्रमुख ने मानवाधिकार परिषद के सत्र में चीन के 'नस्लीय एकीकरण कानून' को रद्द करने की मांग की

**२० जून, २०२६**

**जिनेवा, १५ मई।** संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के ६२वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया मानवाधिकारों से जुड़ी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। आज दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बढ़ रहा है और बुनियादी आजादी पर दबाव है।

तुर्क ने जिनेवा में सदस्य देशों के सामने अपनी वैश्विक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय 'अंतरराष्ट्रीय कानून पर अभूतपूर्व और बेशर्म हमले' का गवाह बन रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को तकलीफ हो रही है। तुर्क ने प्रतिनिधियों से कहा, 'हमें हर बार और हर जगह इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इसे रोकने व खत्म करने के लिए काम करना चाहिए।' उन्होंने बढ़ते वैश्विक संकटों के बीच अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

उच्चायुक्त ने साथ ही दुनिया भर में मानवाधिकार तंत्रों के लगातार प्रभाव पर जोर देते हुए कहा कि 'मानवाधिकारों के काम के व्यावहारिक पहलू हर दिन लाखों लोगों को सुरक्षा, सम्मान और आजादी दिला रहे हैं।' उनके संबोधन में जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया, उनमें चीन में मानवाधिकारों की स्थिति, विशेष रूप से बीजिंग के आतंकवाद-रोधी उपायों और नस्लीय व धार्मिक अल्पसंख्यकों पर आत्मसातीकरण की नीतियों का प्रभाव शामिल था।

तुर्क ने चीन द्वारा हाल ही में पारित किए गए 'नस्लीय एकीकरण और प्रगति को बढ़ावा देने वाले कानून' पर गंभीर चिंता व्यक्त की और चेतावनी दी कि यह कानून अल्पसंख्यक समुदायों पर मौजूदा प्रतिबंधों को और बढ़ा सकता है।

उन्होंने कहा, 'मैं चीन की आतंकवाद-रोधी और आत्मसातीकरण नीतियों को लेकर बहुत चिंतित हूं, खासकर इसलिए क्योंकि ये झिंझियांग, आंतरिक मंगोलिया और तिब्बत क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को प्रभावित करती हैं।'

उच्चायुक्त के अनुसार, इस कानून से भाषा, शिक्षा, धार्मिक रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण सभा करने से जुड़ी आजादी के और सीमित होने का खतरा है। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यापक रूप से तैयार किए गए प्रावधानों के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए भी सजा दी जा सकती है।

तुर्क ने चीनी अधिकारियों से इस कानून को रद्द करने और नस्लीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करने वाली नीतियों को खत्म करने का आह्वान किया।

उनकी चिंताएं संयुक्त राष्ट्र के कई स्वतंत्र विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों से मिलती-जुलती हैं। इन संगठनों का तर्क है कि यह कानून विलय करने की नीतियों को संस्थागत बना सकता है और तिब्बती, उग्यूर और मंगोलियाई जैसे अल्पसंख्यक समुदायों की सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक पहचान की सुरक्षा को कम कर सकता है। चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस द्वारा मार्च २०२६ में पारित किए गए और ०१ जुलाई २०२६ से लागू होने वाले इस कानून का मकसद राष्ट्रीय एकजुटता को मजबूत करना और एक एकीकृत राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देना बताया गया है। चीनी अधिकारियों का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य सामाजिक स्थिरता, राष्ट्रीय एकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि यह कानून शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में मंदारिन भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली पुरानी नीतियों को औपचारिक रूप देता है, जबकि अल्पसंख्यक भाषाओं, परंपराओं और धार्मिक रीति-रिवाजों के लिए गुंजाइश कम करता है।

तुर्क की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए जिनेवा स्थित तिब्बत कार्यालय में परम पावन दलाई लामा की प्रतिनिधि थिनले चुक्की ने उच्चायुक्त के हस्तक्षेप का स्वागत किया और इस बयान को समयोचित और महत्वपूर्ण बताया।

चुक्की ने कहा कि यह कानून उन नीतियों को और आगे बढ़ाता है, जिनके बारे में तिब्बती पक्षधरता समूहों का कहना है कि वे दशकों से तिब्बती धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि इस कानून के संभावित असर चीन की सीमाओं से बाहर तक फैल सकते हैं, जिससे सीमा पार दमन और विदेशों में रहने वाले तिब्बतियों पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं पैदा हो सकती हैं।

चुक्की ने कहा, 'यह कानून न केवल चीन के भीतर तिब्बती पहचान के लिए खतरा है, बल्कि इसके असर चीन की सीमाओं से बाहर भी हो सकते हैं।' उन्होंने कहा कि इस कदम से प्रवासी समुदायों पर असर पड़ सकता है और अन्य देशों के लिए व्यापक चिंताएं पैदा हो सकती हैं।

मानवाधिकार संगठनों और यूरोपीय संसद सहित कई अंतरराष्ट्रीय निकायों ने भी इसी तरह की चिंताएं व्यक्त की हैं कि नस्लीय एकीकरण से संबंधित प्रावधान देश और विदेश दोनों जगहों पर अल्पसंख्यक समुदायों की निगरानी और उन पर नियंत्रण बढ़ा सकते हैं।

चीन ने झिंझियांग और तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को लगातार खारिज किया है और कहा है कि चरमपंथ से निपटने, विकास को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए इस तरह की नीतियां जरूरी हैं।

उम्मीद है कि मानवाधिकार परिषद में चर्चाओं के दौरान यह मुद्दा मुख्य केंद्र में बना रहेगा, क्योंकि सदस्य देश, विशेषज्ञ और नागरिक समाज संगठन अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों और अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन पर बहस करेंगे।

- जिनेवा स्थित तिब्बत कार्यालय की रिपोर्ट

## ◆ १८. आत्मदाह करने वाले तिब्बतियों का स्मरण

བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ།

तेनजिन खेड़ुप

पेशा-पूर्व भिक्षु

विरोध की तारीख - २० जून २०१२

स्थान- जातो, युलशुल, अमदो

उम्र-२४

वर्तमान स्थिति- दिवंगत

ངག་དབང་ནོར་འཕེལ།

न्गावांग नोरफेल

पेशा- पूर्व भिक्षु

विरोध की तारीख- २० जून २०१२

स्थान- जातोए, युलशुल, अमदो

उम्र- २२ वर्ष

वर्तमान स्थिति- अज्ञात

२० जून २०१२ को २४ वर्षीय तेनजिन खेंड़ुप और २२ वर्षीय न्गावांग नोरफेल ने चीनी शासन का विरोध करने के लिए जातोए, युलशुल में आत्मदाह कर अपनी जान दे दी। तिब्बती राष्ट्रीय झंडे लेकर उन्होंने तिब्बत की आजादी और परम पावन १४वें दलाई लामा की तिब्बत वापसी के पक्ष में नारे लगाए। अपने आखिरी संदेश में उन्होंने युवा पीढ़ी से एकजुट रहने और तिब्बती धर्म, संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए लगन से काम करते रहने की अपील की। उनका गहरा बलिदान आजादी और इंसानी सम्मान के लिए तिब्बतियों के सामूहिक संघर्ष का एक पक्का सबूत है।

# IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.
Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.
You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.
We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

**Tashi Dekyi**
Coordinator
India Tibet Coordination Office

# आवश्यक सूचना

**प्रिय पाठकों,**

सबसे पहले में, आप सभी का बहुत अभार व्यक्त करता हूं कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदर भागीदारी रहा है।
तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और कूर नीति तथा विश्व स्तर पर परमपावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।
आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नही रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहां से रवाना हो चुका है।
इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे है। और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे है तो उसकी पुष्टी हमे तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीछे लिखे गये पता या ई–मेल पर भेज सकते है।
अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमे समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

**ताशी देकि**
कार्यवाहक समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र
नई दिल्ली


**कार्यलय पताः** भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच–10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर–03, नई दिल्ली–110024
**फोनः** 011–29830578
**ई–मेलः** coordinator@indiatibet.net

June, 2026, Years: 47 Issue: 6 Regd No. : RNI 34636-79

17वें काशाग के छह मंत्री

तिब्बत लॉबी डे पर वॉशिंगटन डीसी में जुटे २२५ तिब्बती और समर्थक, तिब्बत बिल पास करने की अपील